जमीन खरीदने के लिए बैंक से नहीं मिलता कर्ज, अब आगरा एक्सप्रेसवे से ही होगा रकम का इंतजाम

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए धन जुटाने को निकला नया रास्ता

राज्य मुख्यालय | विशेष संवाददाता

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन खरीदने का अब दूसरा व आसान रास्ता निकाला गया है। इसके लिए काफी बड़ी रकम का इंतजाम लखनऊ आगरा- एक्सप्रेसवे से से ही होगा, लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब इस एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन (मुद्रीकरण) के बजाए सिक्योरिटाइजेशन होगा। दूसरे वाले विकल्प से बैंकों से जमीन खरीदने के लिए जल्द व सस्ता कर्ज मिल सकेगा।

असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का काम इस साल जुलाई से शुरू हो जाए। इसके लिए जून तक जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बैंक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से लंबे समय तक आने वाले टोल आमदनी के आधार पर कर्ज दे सकेंगे। इसके बिना जमीन के लिए बैंक से कर्ज मिलना संभव नहीं है।

एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने तय किया है कि एक्सप्रेस-वे के मुद्रीकरण की योजना को फिलहाल स्थगित रखा जाए और सिक्योरिटाइजेशन के जरिए पैसा जुटाया जाए। इससे करीब 4000 करोड़ रुपये का इंतजाम हो जाएगा और जमीन खरीदने का काम आसानी से होता जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए वित्तीय सलाहकार कंपनी एसबीआई कैपिटेल ने सरकार को सिक्योरिटाइजेशन की सलाह दी है। इसी तरह का विकल्प महाराष्ट्र में मुंबई -नागपुर एक्सप्रेसवे के लिए किया है। यह एक्सप्रेसवे 701 किमी लंबा बन रहा है। इसके निर्माण के लिए धन जुटाने को वहां मुंबई पूणे-एक्सप्रेसवे का सिक्योरिटाइजेशन कर लोन लिया जा रहा है।

बढ़ेगा ट्रैफिक तो होगी ज्यादा आमदनी

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पूरा होने पर पूर्वी यूपी व बिहार से आने वाले वाहन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल पश्चिमी यूपी जाने के लिए करेंगे। यही नहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी इटावा से इससे जुड़ जाएगा। इससे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दो साल में ट्रैफिक काफी बढ़ जाएगा। इस कारण इस एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह में भारी इजाफा होगा। उस वक्त इस एक्सप्रेस-वे का मुद्रीकरण करना यूपीडा के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।